मुद्दा

2017-2018 का बजट पेश होने के बाद शेयर बजार 486 अंक उछला। पूंजी बाजार में ऐसा इजाफा आठ साल बाद देखने को मिला। सेंसेक्स देश के विकास का पैमाना न भी हो तो भी यह अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा दर्शाता है। इससे पहले 2009 के बजट के बाद शेयर बाजार में ऐसी तेजी देखने को मिली थी। उस वक्त सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से उबारने की चुनौती थी। लिहाजा कृषि और आधारभूत क्षेत्रों के लिए तमाम प्रावधान हुए। चुनौतियां मौजूदा सरकार के सामने भी कम नहीं। पर अब ये काफी अलग हैं। 'ब्लैक इकोनॉमी' को औपचारिक और पारदर्शी अर्थव्यवस्था में बदलना आसान नहीं। वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए सरकार ने गांव, किसान, आम आदमी के लिए प्रभावी कदम उठाए। स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के साथ आम लोग भी उसकी प्राथमिकता में हैं।

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
05 फरवरी 2017

राजस्व बढ़ाने के साथ ही संसाधनों के प्रबंधन का प्रयोग

महत्वपूर्ण सामाजिक सेक्टरों में सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने की जरूरत है। इससे राज्यों में फैली क्षेत्रीय असमानताओं को कुछ हद तक खत्म करने की दिशा में मदद मिलेगी।

सौम्या श्रीवास्तव
सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी

2017-18 का आम बजट कई मायनों में निराश करने वाला रहा है। इस बजट को देखकर कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री का ध्यान सार्वजनिक खर्च प्रबंधन को सुधारने पर केंद्रित है। जबकि कई सेक्टरों में पिछले बजट के आवंटन की राशि को बढ़ाया नहीं गया है।

आम बजट को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता थी। अनुमान लगाए जा रहे थे कि यह नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को खत्म करने के लिए वित्तीय नीति में विस्तार करेगा। योजनाबद्ध व गैर योजनाबद्ध खर्चों के विलय और बजट पेश होने की तारीख में बदलाव भी चर्चा का विषय बने हुए थे। इन सभी उम्मीदों के उलट, 2017-18 के आम बजट ने वित्तीय नीति में विस्तार नहीं किया। 2016-17 के बजट की तुलना में इस साल कुल खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल का बजट 20.14 लाख करोड़ का था जो इस साल 21.47 लाख करोड़ हो गया। 1.32 लाख करोड़ की वृद्धि में से 40 हजार करोड़ का उपयोग बढ़ी हुई ब्याज दरों के तहत भुगतान के लिए होगा। 35 हजार करोड़ को विभिन्न सेक्टरों में पूंजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन खर्चों के बाद सौ विभागों में बांटने के लिए 75 हजार करोड़ से कम राशि बचती है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में केंद्र सरकार का कुल व्यय 2016-17 में 13.4 फीसद से घटकर 2017-18 में 12.7 फीसद रह गया है। 2012-13 के बाद से यह सबसे कम है। इस लिहाज से कहा जाए तो 2017-18 का बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कुछ सरकारी योजनाओं के बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई। दूसरी तरफ सामाजिक विकास की अन्य योजनाओं के आवंटन में नाममात्र वृद्धि की गई। उदाहरण के लिए 2016-17 के संशोधित अनुमानों (रिवाइज्ड एस्टीमेट्स) के अनुसार 2017-18 के बजट में सर्व शिक्षा अभियान के मद में केवल एक हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। मिड डे मील के लिए 300 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ और मनरेगा के लिए 500 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सबला, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी कई योजनाओं के लिए 2017-18 के अनुमानित बजट में 2016-17 की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में देखा जाए तो शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के बजट में इस समयावधि में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

अहम क्षेत्रों की अनदेखी

इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यह बजट इन क्षेत्रों में आवंटन बढ़ाने पर नहीं बल्कि आम लोगों के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने और फंड के प्रवाह को बढ़ाने व संसाधनों के प्रयोग पर केंद्रित है। यह सभी अच्छे उपाय हैं, लेकिन सिर्फ इनके जरिए सुधार नहीं आ सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि फंड के निष्प्रभावी उपयोग के पीछे बड़े कारण हैं। इनमें स्टाफ की कमी और विकेंद्रीकृत योजनाओं में कमियां शामिल हैं। राज्य स्तर पर सार्वजनिक और सामाजिक सेक्टरों पर होने वाले खर्च को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में असमानताएं हैं। ऐसे में इन सेक्टरों के प्रति केंद्र सरकार की प्राथमिकता कम होना चिंता का विषय है। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी द्वारा बजट के विश्लेषण में यह साफ हुआ कि सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण विकास, कृषि व अन्य संबंधी क्षेत्रों के लिए 2016-17 के अनुमानित बजट में दस राज्यों में 6,287 करोड़ से 14,223 करोड़ रुपये के बीच आवंटन किया गया।

सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की जरूरत

बिहार और उत्तर प्रदेश जहां इस सूची में सबसे पीछे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने सबसे ज्यादा खर्च किया। लिहाजा जहां एक ओर कुछ ही राज्य सामाजिक क्षेत्र में खर्चे को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खर्च करने की क्षमता में काफी फर्क है। इसलिए सरकार को महत्वपूर्ण सामाजिक सेक्टरों में सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने की जरूरत है ताकि राज्यों में फैली क्षेत्रीय असमानताओं को कुछ हद तक खत्म किया जा सके। आम बजट में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो दो चिंताओं को जन्म दे रहा है। यह बदलाव है योजनागत और गैर-योजनागत खर्च का विलय। पहली चिंता इस बात की है कि अब राजस्व और पूंजी खर्च के वर्गीकरण पर अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा।

प्रभावित हो रहा सामाजिक क्षेत्र

यह स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक सेक्टरों के लिए समस्या बन सकता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च को राजस्व खर्च बताया जाता है। इसमें तनख्वाह, प्रशिक्षण, संचालन और संरक्षण पर होने वाला खर्च शामिल है। इसी के साथ वित्तीय नीतियों को सख्त कर दिया गया है। अब तक इन सेक्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में थोड़ा बहुत फेरबदल कर लिया जाता था, जो कि अब नहीं हो सकेगा। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम, 2003 केंद्र और राज्य सरकारों से वित्तीय घाटे को कम करने और राजस्व घाटे को हटाने की अपेक्षा रखता है। नतीजतन फिलहाल कई राज्य पूंजी में से खर्च को प्राथमिकता देकर राजस्व में मुनाफा कमा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कुछ राज्य अपने राजस्व खर्च को कम करके पूंजीगत खर्च को बढ़ा रहे हैं। साथ ही राजस्व खर्च के जरिए मिलने वाली अतिरिक्त धनराशि का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए हो रहा है। इससे सामाजिक क्षेत्रों में फंडिंग सर्वाधिक प्रभावित हो रही है।

दूसरी चिंता है अनुसूचित जाति सब प्लान व जनजाति सब प्लान। देश में अनुसूचित जाति व जनजाति की आबादी के आधार पर बजट में इन योजनाओं के लिए आवंटन किया गया है। लेकिन गैर-योजनागत खर्च का प्रावधान खत्म हो जाने से जरूरत पड़ने पर इन योजनाओं के फंड में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इस बजट में अनुसूचित जाति सब प्लान व जनजाति सब प्लान के तहत फंड को 'अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु' नाम दिया गया है। ऐसा करने से अनुसूचित जाति व जनजाति को उनके अधिकार देने की बात करने वाली यह योजनाएं अब केवल उनके कल्याण की बात कर रहीं हैं। इससे इन योजनाओं का मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया है। आम बजट कई मायनों में निराश करने वाला रहा है। इस बजट को देखकर कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री का ध्यान सार्वजनिक खर्च प्रबंधन को सुधारने पर केंद्रित है।